आर्थिक वृद्धि पर संदेह करने वाले 'वक्रदृष्टा'

पांच दिवसीय यूपी ट्रेड शो में 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद

वीरेंद्र सिंह रावत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों पर संदेह जताने वालों को 'वक्रदृष्टा' यानी नकारात्मक सोच रखने वाले लोग बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन सरकार' की भी सराहना की। शाह ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में जगह-जगह बने अवैध हथियार कारखानों की जगह अब छह विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्रों वाला बड़ा रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया गया है।

शाह ने कहा कि यह बदलाव 'डबल इंजन सरकार' के तहत हुआ है और आज उत्तर प्रदेश देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश केंद्र बन रहा है। शाह पांच दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे और इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि हाल की तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी आर्थिक वृद्धि इस बात का सबूत है कि देश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अब भी सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'दुनिया में उथल-पुथल और कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपना विकास जारी रखा है और इसे आगे बढ़ाया है।'

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर देती है। अमेठी में बनी एके-203 असॉल्ट राइफल 'नक्सलियों और आतंकवादियों' के खिलाफ एक प्रमुख हथियार बन गई है। उन्होंने कहा कि 'अपराध के पहले के माहौल से रक्षा निर्माण, वाहन उत्पादन और चिकित्सा-उपकरण निर्माण के क्षेत्र में परिवर्तन' उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

चौथे यूपीआईटीएस में में 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदार भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें भाग रहे 2,400 से अधिक कारोबारी या कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) आगंतुकों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पांच दिन के इस आयोजन में 2025 के मुकाबले अधिक लोग पहुंचेंगे। 2025 के संस्करण में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे और 400 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुए थे।



गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

शाह ने कहा कि भारत ने वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद न केवल अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे और मजबूत भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश की विकास दर के अनुमान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआर) द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग को हाल में बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों की भारत के आर्थिक प्रदर्शन की आलोचना को लेकर निंदा की, जिसमें पहली तिमाही में दर्ज की गई 7.8 फीसदी वृद्धि भी शामिल है। शाह ने कहा, 'कुछ 'वक्रदृष्टा' सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर विवाद करते रहते हैं। जिनकी सोच ही मरी हुई है, वे जीवंतता नहीं देख सकते, उन्हे हर जगह सब कुछ मृत ही नजर आजा है।' यह कहते हुए उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 31 जुलाई 2025 के उस बयान का इशारा किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि 'भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है' और एक्स पर एक पोस्ट में पीएम पर इसे 'मारने' का आरोप लगाया था।

केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत की ओर से किए गए और जिन देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय कारोबारियों के लिए निर्यात के नए अवसर खुले हैं। शाह ने निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2013 में उत्तर प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था के कारण लखनऊ में निवेश सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका था और इसे दिल्ली में आयोजित करना पड़ा था। शाह ने कहा, 'निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति, सक्रिय सरकार और उद्योग के अनुकूल रवैया जरूरी है। आज ये सभी स्थितियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और राज्य ने एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखा है।'

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीआईटीएस का चौथा संस्करण 'नए उत्तर प्रदेश' की क्षमता को देखने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पारंपरिक कौशल को तकनीक, निवेश और वैश्विक बाजारों से जोड़कर राज्य की पहचान बदली है। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में क्षमता की कभी कमी नहीं रही। जरूरत सिर्फ इसकी पहचान करने, सही माहौल तैयार करने और इसे बड़े स्तर तक ले जाने की थी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, हवाई अड्डे, माल ढुलाई गलियारे और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे निवेश, उत्पादन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए अवसर पैदा हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल ने पारंपरिक कारोबार को एक अलग पहचान दिलाई है और उत्तर प्रदेश को विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि राज्य अब दुनिया के अलग-अलग बाजारों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सामान निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले यूपीआईटीएस में 75 देशों के 550 खरीदार शामिल हुए थे। इस साल करीब 90 देशों के खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें 600 से अधिक विदेशी खरीदार होंगे। आयोजन में करीब 1.5 लाख बी2बी आगंतुकों के आने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान, रूस, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और बेलारूस इस आयोजन में साझेदार देशों के रूप में शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'इन देशों के पवेलियन से रणनीतिक साझेदारी, तकनीक के आदान-प्रदान और संयुक्त उद्यम के अवसर मिलेंगे।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से उत्तर प्रदेश के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे राज्य विदेशी कंपनियों को यहां निवेश और उत्पादन के लिए आमंत्रित कर सकता है, ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकें। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी 79 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला हुआ है। इसके अलावा 75 और उत्पादों के लिए आवेदन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के सामान, कन्नौज के इत्र और वाराणसी की रेशमी साड़ियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो से कारीगरों को विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है।

उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आयोजन में 2,400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें रक्षा, कृषि, उद्योग, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), शिक्षा, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, डेरी, हथकरघा, कपड़ा और विभिन्न जीआई उत्पाद प्रमुख आकर्षण हैं। उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री ब्रजेश सिंह और एमएसएमई के राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

चुनाव आयोग मामला

राजग सहयोगियों ने मांगा स्पष्टीकरण



भाजपा के तीन सहयोगी दलों लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव व्यवस्था पर लोगों का भरोसा दांव पर है। पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि वह न तो चुनाव आयोग के लिए बोल रहे हैं और न ही विपक्ष के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता के सामने अब जो सवाल हैं, उनके लिए आयोग से स्पष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की, जबकि टीडीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्णा देवरायालु ने कहा कि पारदर्शिता संवैधानिक संस्था में विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। इनकी टिप्पणियां 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद आईं, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन निर्णयों और आदेशों पर लिखित आपत्ति जताई है, जिन्हें उन्होंने उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किया गया बताया था।

इन आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का प्रबंधन और मतदाता सूची के डेटाबेस पर केंद्रीकृत नियंत्रण से जुड़े मामले शामिल थे। इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची के एसआईआर को रोकने की मांग की है। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार के एक हिस्से के रूप में मेरा इरादा किसी संवैधानिक निकाय का बचाव करना नहीं है। मैं विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी बहुत चिंतित नहीं हूं, जो हमेशा वही रुख अपनाएगा जो राजनीतिक रूप से उसके लिए फायदेमंद हो।' उन्होंने कहा, 'यदि लोग चुनावी प्रणाली में विश्वास खोना शुरू कर देते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपना स्पष्टीकरण अधिक मजबूती से देनी चाहिए। उसे राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे लोगों के मन से गलतफहमियों को दूर करना चाहिए।'

टीडीपी के देवरायालु ने कहा कि हालांकि आंध्र प्रदेश में एसआईआर पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था, चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा, 'आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण से एसआईआर अभ्यास को करीब से देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई थी। हर मतदाता को भाग लेने और चिंताएं उठाने के लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय प्रदान किया गया था।' उन्होंने कहा, 'अभ्यास सफल रहा है। यहां तक कि विपक्ष भी आंध्र प्रदेश में प्रक्रिया के संबंध में चिंताओं को सही साबित नहीं कर पाया है। साथ ही, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, जब भी किसी के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, तो उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने और पारदर्शिता बनाए रखने से संस्था में जनता का विश्वास मजबूत होगा।'

आरएलएम के कुशवाहा, जो एक राज्यसभा सांसद हैं, ने कहा कि विवाद ने लोगों के बीच भ्रम पैदा किया है। एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, 'एसआईआर को लेकर विवाद ने जनता के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इस मामले को संबोधित करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को इस भ्रम को दूर करने के लिए वास्तविक स्थिति के संबंध में तत्काल स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए।' एजेंसियां

ट्राई ने शुरू किया इनडोर डेटा कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म

डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 70-80 फीसदी डेटा खपत घरों के अंदर

गुलवीन औलख

भारतीय दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने शुक्रवार को 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म' शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता, प्रॉपर्टी डेवलपर और संपत्ति के मालिक इमारतों की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग देख सकेंगे। नियामक ने इमारतों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी जांचने के लिए एक ऐप भी शुरू किया है, जो बेहद अहम है क्योंकि आजकल लगभग 70-80 फीसदी मोबाइल डेटा का उपयोग घरों और दफ्तरों के अंदर होता है।

ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने शुक्रवार को कहा, 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत संपत्ति के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी को अधिक मापने योग्य, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह बेहतर योजना बनाने, हितधारकों के बीच तालमेल में सुधार करने और उपभोक्ताओं को संपत्तियों की कनेक्टिविटी ढांचा और प्रदर्शन के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा।'



यह प्लेटफॉर्म घरों, दफ्तरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों के भीतर कनेक्टिविटी की गुणवत्ता को डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी की जानकारी देने के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी जांचने के लिए एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म रेटिंग की पूरी प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म पोर्टल और ऐप दोनों के रूप में काम करेगा। इसका इस्तेमाल संपत्ति प्रबंधक और ग्राहक दोनों कर सकेंगे। रेटिंग एक से पांच स्टार के स्तर पर होगी, जिसमें एक स्टार सबसे कम और पांच स्टार सबसे अधिक रेटिंग को दर्शाएगा। नियामक ने निर्माणाधीन संपत्ति के लिए आधे स्टार की रेटिंग का विकल्प भी रखा है।

संपत्ति प्रबंधक इस प्लेटफॉर्म पर अपना और संपत्ति का पंजीकरण कर सकते हैं, रेटिंग के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, पंजीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी का चयन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए) पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। वे उन्हें आवंटित संपत्ति की जानकारी देख सकेंगी, उसका आकलन कर सकेंगी, अपनी टिप्पणियां और टेस्ट के नतीजे दर्ज कर सकेंगी और जरूरी दस्तावेज प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगी। संपत्ति का मौके पर आकलन डीसीआरए के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप के जरिये किया जाएगा। अधिकृत डीसीआरए इस ऐप का इस्तेमाल तय जांच प्रक्रिया के अनुसार इमारत के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की जांच के लिए कर सकेंगी।

नियामक ने कहा कि ग्राहकों के लिए प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रेटिंग सर्च पेज उपलब्ध होगा। यहां उपभोक्ता संपत्ति के नाम या स्थान के आधार पर उसकी रेटिंग खोज सकेंगे। इससे उन्हें इमारत की डिजिटल कनेक्टिविटी के आधार पर खरीद या किराये का फैसला लेने में मदद मिलेगी। नियामक ने कहा कि इससे घर या संपत्ति खरीदने और किराये पर लेने के फैसलों में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप के जरिये किए गए डिजिटल कनेक्टिविटी टेस्ट का विवरण प्लेटफॉर्म पर अपने आप दर्ज हो जाएगा।

यह प्लेटफॉर्म तैयार हो चुकी और निर्माणाधीन दोनों तरह की संपत्तियों की रेटिंग की सुविधा देता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

क्षेत्रीय कार्यालय: द्वितीय तल, भारतीय स्टेट बैंक के पास, नयापुरा, कोलार रोड, अकबरपुर, मेन कोलार रोड, भोपाल -462042
फोन : 0755-4249988, 4243700, 4203836

QR CODE FOR SERVICE PROVIDER

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.10.2026 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 54) के अंतर्गत बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार हमारी शाखा में निम्नलिखित ऋण खातों में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है, जिन्हें बैंक के बकाया की वसूली के लिए ''जैसा है जहाँ है, जिस स्थिति में है और जो कुछ भी वहाँ मौजूद है'' बेचने का अधिकार है। बिक्री https://www.Baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा / खाते / ऋणी / जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	Qr Code For Property Image/video	Qr Code For Property Location	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि (रु.) +भविष्य में देय ब्याज एवं अन्य खर्च
	पीवाय रोड शाखा, इंदौर फोन : 0731-2340490, प्राधिकृत अधिकारी : नबा गोपाल सामल, 9039170111					
1.	ऋणी- **श्री रविन्द्र सोलंकी पुत्र मदनलाल एवं श्रीमती भगवती सोलंकी पत्नि श्री रविन्द्र सोलंकी**	संपत्ति का समस्त भू भाग स्थित प्लाट नं. 68 बी, सिटी एवं कस्बा - गिरनार सिटी, ग्राम- छोटा बांगदड़ा, इंदौर जिला- इंदौर चर्तुसीमाएं- उत्तर- प्लाट नं. 869, दक्षिण- रोड, पूर्व- प्लाट बी-87, पश्चिम- प्लाट बी-76 कब्जे का प्रकार - सांकेतिक			₹ 86,70,000/- ₹ 8,67,000/- ₹ 86,700/-	दिनांक : 30.12.2025 ₹ 62,25,548.99 +ब्याज एवं अन्य खर्च

संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय : 28.10.2026 (सुबह 10.00 से दोपहर 3.00 बजे तक)
ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की दिनांक 29.10.2026 शाम 6.00 बजे तक

बोलीदाताओं द्वारा ईएमडी को ई-नीलामी पोर्टल अर्थात www.Baanknet.com/ पर उपलब्ध कराए गए अपने वॉलेट में एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।
खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है: ,खाते का नाम-एनईएफटी पार्किंग खाता; खाता संख्या-80215040070003; आईएफएस कोड- PSIB0008021
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list & https://www.Baanknet.com देखें
इस नोटिस को नियम 8(6) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन), नियम 2002 के तहत ऋणियों एवं जमानतदारों (एल/आर) को 30 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।
दिनांक : 24.09.2026 स्थान- इंदौर प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

मुंबई: आवासीय संपत्ति की कीमतें बढ़ीं

प्राची पिसाल

नाइट फ्रैंक के 'प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स' में मुंबई 2026 की दूसरी तिमाही में विश्व में आठवें स्थान पर रहा। मुंबई की प्रमुख आवासीय संपत्ति की कीमतों में सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी 46 शहरों वाले इस सूचकांक में दर्ज की गई 2.6 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि दर से दोगुनी से भी ज्यादा है।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में मुंबई की प्रमुख आवासीय संपत्ति की कीमत सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत बढ़ीं। भारत के अन्य शहरों में बेंगलूरु 4.5 प्रतिशत की सालाना मूल्य वृद्धि के साथ दुनिया भर में 12वें स्थान पर रहा। हालांकि नई दिल्ली 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17वें स्थान पर रहा। भारत के ये तीनों शहर दुनिया के शीर्ष 20 मार्केट में शामिल रहे।



नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनैशनल पार्टनर, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि मुंबई की 6.2 प्रतिशत की वृद्धि शीर्ष स्तर पर उच्च मांग को उजागर करती है। उन्होंने कहा, 'इस शहर में 6.2 प्रतिशत की सालाना वृद्धि मार्केट के ऊपरी हिस्से में मजबूत मांग को दर्शाती है, जहां लोकेशन, गुणवत्ता और अलग तरह की आवासीय पेशकशें कीमतों को मदद दे रही हैं। यह निवेशकों और खरीदारों के लिए पुष्टि करता है कि मुंबई की मार्केट की मुख्य आवासीय संपत्तियां लंबे समय में संपत्ति बनाने और सीमित आपूर्ति से गहराई से जुड़ी हुई हैं।'

वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक के एक साल में वैश्विक मुख्य आवासीय प्रापर्टी की कीमतों में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2026 की पहली तिमाही तक के एक साल में यह सालाना वृद्धि 2 प्रतिशत थी। वैश्विक रैंकिंग में टोक्यो सबसे आगे रहा, जहां प्रमुख घरों की कीमतों में सालाना 50.7 प्रतिशत और तिमाही में 12.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद मनीला का नंबर रहा, जहां सालाना 14.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुबई 10.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान और सिंगापुर 9.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ चौथे स्थान पर रहा।

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

ग्राहक हेतु परामर्श

कृपया ध्यान दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का प्रस्ताव रखा है।

हालांकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक प्रस्तावित हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हड़ताल की तारीखों से पहले ही महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पूर्ण कर लें। हमारे डिजिटल चैनल जैसे पीएसबी यूनिक, नेट बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और कारोबार प्रतिनिधि आपकी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे।

इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए, हमारी सभी शाखाएं 27.09.2026 (रविवार) को खुली रहेंगी और संचालन करेगी।

हम आपको हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक